राष्ट्रीय · National

यूपी पेंशन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नए माइनिंग प्लान दिशा-निर्देश व निर्यात दिशा संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के दो पेंशन कानूनों को किया रद्द, कोयला मंत्रालय ने जारी किए माइनिंग प्लान 2026 दिशा-निर्देश और निर्यात दिशा योजना में हुआ बड़ा संशोधन।

राष्ट्रीय · National

1. यूपी पेंशन कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- उत्तर प्रदेश के 2021 और 2025 के पूर्वव्यापी पेंशन कानून असंवैधानिक घोषित हुए।
- नियमित कर्मचारियों की पिछली दैनिक वेतनभोगी सेवा भी पेंशन में गिनी जाएगी।
- अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत कर्मचारियों के अधिकारों को संरक्षण मिला।

राष्ट्रीय · National

2. माइनिंग व माइन क्लोजर दिशा-निर्देश 2026

- कोयला मंत्रालय ने कोयला व लिग्नाइट खदानों के लिए नए नियम जारी किए।
- एस्क्रो खाते से प्रतिपूर्ति की समय-सीमा घटकर केवल 1 माह हुई।
- अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन (UCG) को आधिकारिक खनन पद्धति का दर्जा।

राष्ट्रीय · National

3. निर्यात दिशा उप-योजना में बड़े सुधार

- हवाई किराये प्रतिपूर्ति हेतु टर्नओवर सीमा ₹75 लाख से बढ़कर ₹50 करोड़ हुई।
- सूक्ष्म व लघु निर्यातकों को हवाई किराये में 95% तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी।
- गुणवत्ता प्रमाणन सूची 462 से बढ़कर 600 हुई, ईपीसी सदस्यता अवधि 3 माह तय।

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक पेंशन वाद	यूपी ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट नॉन-गजेटेड एम्प्लॉईज एसोसिएशन बनाम मुख्य सचिव
उल्लंघन पाए गए संवैधानिक अनुच्छेद	अनुच्छेद 14, 16 और 21
एस्क्रो प्रतिपूर्ति की नई समय-सीमा	दावा प्राप्ति से 1 माह
निर्यात प्रोत्साहन मिशन (EPM) परिव्यय	₹25,060 करोड़ (2025-26 से 2030-31)
सूक्ष्म व लघु निर्यातकों को हवाई किराया सहायता	95% तक
ट्रेस (TRACE) के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र	600 प्रमाणपत्र

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2026 में उत्तर प्रदेश के किन पेंशन कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन मानते हुए रद्द किया?

A उत्तर प्रदेश पेंशन संशोधन अधिनियम 2018 और 2020

B उत्तर प्रदेश अर्हकारी सेवा अधिनियम 2021 और पेंशन पात्रता अधिनियम 2025

C उत्तर प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2015

D उत्तर प्रदेश तदर्थ कर्मचारी पेंशन संरक्षण अधिनियम 2023

उत्तर / Answer: B — सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 और 2025 के पात्रता अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

कोयला मंत्रालय द्वारा जारी खदान योजना एवं खदान बंदी दिशा-निर्देश 2026 के अनुसार एस्क्रो खाते से प्रतिपूर्ति की समय-सीमा कितनी तय की गई है?

A 1 माह

B 3 माह

C 6 माह

D 15 दिन

उत्तर / Answer: A — नए नियमों के तहत खदान बंदी कार्यों के लिए एस्क्रो खाते से प्रतिपूर्ति की समय-सीमा दावा प्राप्ति के 1 माह के भीतर तय की गई है।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends